राजनीतिक तरकस

RNI NO.: DELHIN/2016/70363

देश का सबसे तेज साप्ताहिक

मूल्य : ₹5

■ वर्ष : 01 ■ अंक : 03 ■ पृष्ठ : 08 ■ नई दिल्ली

■ बुधवार ■ 12 अक्टूबर , 2022 (12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2022)

राष्ट्रीय विचार, सटीक समाचार

www.rajneetiktarkas.in

सफल उद्यमी, कुशल रणनीतिकार, वैदिक संस्कृति एवं संस्कारों का जानकार

भारतीय राजनीति का उभरता किरदार

राकेश शुक्ल

जितेंद्र तिवारी

प्रधान संपादक

भारत का वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य भारत की पुरातन संस्कृति और परम्पराओं के तहत आने वाले राजनीतिक परिवेश को पुनः चरितार्थ करता दिखाई पड़ता है, यह कथन मात्र इसलिये नहीं है कि किसी भावना में बहकर इस समाचार को लिखा जा रहा हो, बल्कि वास्तव में वर्तमान भारतीय राजनीति अपनी पुरातन वैदिक परम्पराओं की ओर जा रही है और धीरे-धीरे अपनी पुरातन पहचान को समूचे भारतीय उपमहाद्वीप में स्थापित कर रही है। वर्तमान भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वास्तव में भारत तथा विश्व के समक्ष भारत के एकमात्र ऐसे राजनेता के रूप में उभर कर सामने आये हैं, जो पुरातन भारतीय मूल्यों को स्वयं में समाहित कर उसे भारत की घरा पर कुशलतापूर्वक उतार रहे हैं और विश्व को उन पुरातन भारतीय मूल्यों से परिचित करा रहे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी के समान ही पुरातन वैदिक परम्पराओं की जड़ों से जुड़े उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ भी एक कुशल एवं सफल राजनेता के रूप में उभरकर देश के समक्ष उपस्थित हुये हैं, जो भगवान शिव द्वारा स्थापित तथा शिव अवतार गुरु गोरक्षनाथ द्वारा विस्तारित ' नाथ सम्प्रदाय' के वर्तमान प्रमुख महन्त एवं हिन्दू धर्म के एक कर्मठ नायक माने जाते हैं। पुरातन भारतीय वैदिक परम्पराओं से जुड़े इन्हीं दोनों महानायकों के समान ही एक और राजनेता भारतीय राजनीति में उभर रहा है, जो मूलरूप से भारतीय सनातन परम्पराओं एवं संस्कृति से जुड़ा हुआ है और कुशल डिप्लोमेट तथा सफल उद्यमी लोगों के साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय संगठन से भी सम्बद्ध है।

जनसामान्य के प्रति बुनियादी चिन्तन के चलते आमजन के जीवन से जुड़े रहने वाले, लोकसेवी, प्रखर वक्ता,विनम्र लेखक, राष्ट्रचिन्तक, राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा के कारण भारत भाग्योदय एवं वैश्विक अभ्युदय के लिए दृढ़संवल्पित राकेश शुक्ल ने भारतवर्ष को एक सशक्त राष्ट्र बनाने हेतु गो आधारित स्वावलंबी भारतीय शिक्षा व्यवस्था के प्राद्योगिक केन्द्रों का निर्माण, वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षित करने, सुसंस्कारी नई पीढ़ी का निर्माण करने, धर्मतंत्र, अर्थतंत्र, मनीषातंत्र एवं शासनतंत्र में सार्थक सहगमन कराने, समान विचारधारा युक्त लोकसेवी संस्थाओं में समन्वय बनाने, किशोरो-युवाओं व नारी शक्ति का प्रतिभा, परिष्कार कर उन्हें उद्यमशील बनाने, कन्या शक्ति के महत्व को जनमानस में बिठाने, राष्ट्र के आध्यात्मिक उत्कर्ष का अभियान चलाने तथा इस हेतु आवश्यक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करने जैसे कार्यक्रमों को अपने हाथ में लिया हुआ है।

(शेष पृष्ठ >>2 पर)

राजनीतिक तरकस
देश का सबसे तेज साप्ताहिक
समय से संवाद
वर्ष : 01 , अंक : 03, नई दिल्ली, बुधवार, 12 अक्टूबर, 2022

कुशल राजनेता की भूमिका में जनसेवक राकेश शुक्ला

(पृष्ठ >> 1 का शेष)

राकेश शुक्ल विश्व में फैले प्रवासी भारतीयों की मेघाशक्ति, धनशक्ति एवं जनशक्ति का स्वदेश, प्रकृति एवं मानवता के हित में नियोजन कराने के कार्यक्रमों को करते रहते हैं। वे विश्व भर में फैले भारत के इन सांस्कृतिक दूतों, विशेषरूप से विदेशों में जन्मे भारतीय संस्कृति और उसकी चेतना से जोड़े रखने और उनके माध्यम से विश्वबंधुत्व के प्रभावशाली वातावरण का विनिर्माण करने हेतु विदेशों में भी कार्यरत रहते हैं।

राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर राकेश शुक्ल ने अपनी अभूतपूर्व छाप छोड़ी है, उन मंचों पर इन्होंने सनतान संस्कृति एवं प्राचीन भारतीय वैदिक मूल्यों का भी प्रतिनिधित्व किया है और आज भी वे इस प्रकार के कार्यों को करने में सदैव अग्रणी है। आज जहां रातनीति महत्वकांक्षी राजनीति की ओर परिवर्तित हो रही है, वहीं राजनीति में रहते हुए भी राकेश शुक्ल ने सफल उद्यमी बन कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प आत्मनिर्भर से भारतसिद्धि

तक पहुचाने का कार्य भी किया है और अपने कार्यों एवं विचारों के माध्यम से सनातनी संस्कृति एवं संस्कारों को देश-विदेश के युवाओं तक पहुंचाने का भी सफल प्रयास किया है।

ज्ञात हो, 2019 में प्रयागराज में आयोजित हुए कुंभ की व्यापक सफलता हेतु देश-विदेशों में जाकर व्यक्तिगत रूप से प्रचार-प्रसार का भार राकेश शुक्ल ने स्वयं उठाया और अपने कुशल रणनीति एवं मृदुल स्वभाव से कुंभ के अन्तिम दिनों तक निरन्तर व्यक्तिगत रूप से दिन रात सक्रिय रहते हुए कुंभ के सभी सेवा कार्यों में अपना विशेष योगदान दिया, जिसके कारण वे साधु-संतों एवं श्रद्धालुओं के आशीर्वाद के विशेष पात्र भी बने। अपनी सनातन संस्कृति एवं संस्कारों का प्रभाव राकेश शुक्ल पर इस स्तर तक है ताकि उन्होंने अपने प्रयाग माघ मेला पर आधारित माघ मेला शीर्षक से एक पुस्तक का लेखन भी किया। सनातन संस्कृति के प्रभावों के चलते कुंभ मेला-2019 के सफल आयोजन के लिए उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा कुंभ गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है।

भाजपा तथा उसके वैचारिक समूह से बड़ी प्रगाढ़ता के साथ जुड़े होने के कारण राकेश शुक्ल उनके सभी कर्णधारों के प्रिय हैं, साथ ही वे मोहन भागवत, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी हृदय से जुड़े हुए हैं और समय-समय पर उनके द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करते हुए भारतीय वैदिक परम्पराओ, वैदिक संस्कृतियों, राष्ट्रीय विचार प्रवाहों, भाजपा, सरकार, देश तथा जनता की हृदय से सेवा करते रहते हैं। उनकी यह सनातनी सोच ही उन्हें जननायक बनने की ओर अग्रसर करती है और उनके सामाजिक व राजनैतिक क्रिया-कलाप भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को उनके बारे में सोचने की ओर इंगित करते हैं कि अब इस उभरते हुए राजनेता को उचित महत्व देते हुए उसे सटीक स्थान प्रदान करना चाहिए।

हर शहर का हो बेहतर नियोजन

बीते दिनों दिल्ली और आसपास के इलाकों में भारी बारिश के एक दिन के बाद ही पानी से भरी सड़कें, रेंगते यातायात, टूटे वाहन और घुटनों तक गहरे पानी में चलने वाले नागरिक जैसे परिचित दृश्य देखने को मिले। दो हफ्ते पहले बेंगलुरु में कई जगहों में भारी जलजमाव की स्थिति थी। ऐसी दुखद स्थितियां शहरी नियोजन की कमियों की तरफ इशारा करती हैं। नालियों की बेहतर निकासी क्षमता की कमी और झीलों व नदियों पर ध्यान न देने के साथ शहरी स्थानों को कंक्रीट में बदलने का जोर हर तरफ दिखता है।

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के अनुसार, बेंगलुरु जैसे शहर ने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में क्वालिटी ऑफ लाइफ मेट्रिक के तहत सौ में से 55।67 स्कोर किया, राजधानी होने के बावजूद दिल्ली 57।56 तक पहुंचा, जबकि भुवनेश्वर का स्कोर सिर्फ 11।57 था। एक आदर्श दुनिया में यह स्थिति अस्वीकार्य है। पश्चिम में 1898 में एबेनेजर हॉवर्ड द्वारा चलाये गये गार्डन सिटी आंदोलन ने शहर के केंद्र में काम के माहौल को विकेंद्रीकृत करने की मांग की थी।

नतीजतन, शहरों को योजनाबद्ध तरीके से डिजाइन किया गया। ऐसे आंदोलन इस विचार से प्रेरित थे कि कामगारों का जीवन स्तर बेहतर हो। अमेरिका में गार्डेन सिटी पड़ोस की अवधारणा के साथ विकसित हुआ, जहां एक स्थानीय स्कूल या सामुदायिक केंद्र के आसपास आवासीय घरों और सड़कों का आयोजन किया गया तथा यातायात कम करने और सुरक्षित सड़कें प्रदान करने पर जोर था।

प्रदूषण और भीड़भाड़ पर नियंत्रण के साथ जैव विविधता बनाये रखने के लिए लंदन में चारों ओर एक महानगरीय हरित पट्टी है। सवाल है कि रिंग रोड और शहरी फैलाव से आगे भारतीय शहरों में ऐसा कुछ क्यों नहीं हो सकता है। पेरिस में '15 मिनट सिटी' का विचार काफी सरल है। इसके तहत हर पेरिसवासी को खरीदारी, कामकाज, मनोरंजन संबंधी जरूरतों को 15 मिनट की पैदल या बाइक की सवारी के भीतर पूरा करने में सक्षम होना चाहिए।

इस सक्षमता का मतलब होगा कि वाहनों की आवाजाही काफी कम हो जायेगी। अगले कदम के रूप में पैदल यात्रियों के लिए बेहतर व्यवस्था देने की आवश्यकता है। बेंगलुरु को एक ऐसे शहर के रूप में फिर से डिजाइन क्यों नहीं किया जा सकता है, जहां यातायात की परेशानी न हो। क्या भोजन के लिए 10 मिनट की डिलीवरी के बजाय काम करने के लिए 10 मिनट की पैदल दूरी बेहतर नहीं होगी?

प्रत्येक भारतीय शहर में आदर्श रूप से एक मास्टर प्लान होना चाहिए, जिसे एक-दो दशक के अंतराल पर अद्यतन किया जाए। इन योजनाओं में किफायती

आवास पर ध्यान जरूरी है। देश में शहरी भूमि उपयोग को बेहतर करने की जरूरत है। सैटेलाइट इमेजरी को देखकर साफ लगता है कि रैखिक बुनियादी ढांचे के साथ धान के खेतों में पसरता जा रहा शहरी विकास अनौपचारिक, अनियोजित और विशाल पड़ोस के साथ खासा बेतरतीब है।

सार्वजनिक भूमि उपलब्धता पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। विश्व बैंक के अनुसार, 2050 तक नागरिकों का जीवन स्तर निराशाजनक करते हुए जलवायु परिवर्तन भारत के सकल घरेलू उत्पाद को तीन फीसदी तक कम कर सकता है। भारत के शहरों को अपनी प्राकृतिक तट रेखाओं और नदी के मैदानों की रक्षा कर, अतिक्रमणों को हटाकर भूमि पर बोझ कम करना शुरू करने की आवश्यकता है। बालू के टीलों की रक्षा करना और मैंग्रोव वनों को संरक्षित करना इस लिहाज से बेहद जरूरी होगा। सभी चालू और भावी शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य से पुनर्विचार करने की आवश्यकता होगी।

हमें शहरपन की भावना को भी स्थापित करना होगा। शायद ऐसा करने का एक तरीका स्पष्ट रूप से अपने निवासियों के लिए शहर के अधिकार (राइट टू द सिटी) का आह्वान करना है। शहरी संसाधनों तक व्यक्तिगत पहुंच सुनिश्चित होना जरूरी है। इसके साथ शहरी विकास को लेकर संस्थागत ढांचे को सुदृढ़ और विकसित करने की दरकार है। फिलहाल देश में स्नातकों के लिए करियर के लिहाज से टाउन प्लानिंग के क्षेत्र में आने का खास आकर्षण नहीं है।

शिक्षा से जुड़ी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अनुसार, भारत को 2031 तक तीन लाख प्लानर्स की आवश्यकता होगी, जबकि अभी केवल पांच हजार टाउन प्लानर ही हैं। देश में महज 26 ऐसे संस्थान हैं, जो टाउन प्लानिंग से जुड़े पाठ्यक्रम चलाते हैं। ये संस्थान फिलहाल देश को हर साल 700 टाउन प्लानर देते हैं। हमारे शहरी नीति निर्माताओं को हमारे शहरी विकास के ऐतिहासिक संदर्भ से अवगत होने की आवश्यकता है।

उन्हें समझना होगा कि कांच की इमारतों या ग्रेनाइट का उपयोग हमेशा उपयुक्त नहीं हो सकता है। यह सवाल भी है कि हमारी ऐतिहासिक वास्तुकला से प्रेरित हमारे शहर स्पष्ट रूप से भारतीय क्यों नहीं दिखते। उत्तर भारत के हर शहर में सार्वजनिक स्थान के रूप में एक बावली क्यों नहीं हो सकती है? दरअसल, हम संगठित निजी संपत्ति द्वारा संचालित शहरी परिदृश्य बना रहे हैं और इस चक्कर में हम अपने शहरों को अधिक मानवीय बनाना भूल गये हैं।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक जितेंद्र तिवारी द्वारा इंप्रेशन प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18/19/20, सी ब्लॉक, सेक्टर 59, नोएडा, उ.प्र.-201301 से मुद्रित तथा ई632/7 सी संगम विहार साउथ दिल्ली -110080 से प्रकाशित। प्रकाशित लेखों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्याय क्षेत्र दिल्ली होगा। प्रधान संपादक : **जितेंद्र तिवारी** प्रबंध संपादक :**राजेश तिवारी**
RNI NO.: DELHIN/2016/70363 Email:tarkasnews@gmail.com Mob:9990170069 Website: www.rajneetiktarkas.in

राजनीतिक तरकस
देश का सबसे तेज साप्ताहिक
राष्ट्रीय विचार, सटीक समाचार
वर्ष : 01 , अंक : 03, नई दिल्ली, बुधवार, 12 अक्टूबर, 2022

क्या कांग्रेस में वास्तविक लोकतंत्र आ सकेगा ?

सुरेश हिंदुस्थानी

कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर नेताओं में जिस प्रकार से उत्सुकता बढ़ रही है, उसी प्रकार से कई नेता अपने आपको इस पद के लिए दावेदार मानने लगे हैं। यह केवल इसलिए भी हो रहा है कि कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव एक अप्रत्याशित घटना मानी जा रही है। लम्बे समय से लोकतांत्रिक पद्धति से बहुत दूर रही कांग्रेस पार्टी वास्तव में लोकतंत्र को स्वीकार करेगी, ऐसी संभावना भी बहुत कम दिखाई दे रही है। क्योंकि अभी से कहा जा रहा है कि गांधी परिवार का कोई शुभचिंतक ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा?

इस बात का आशय यही है कि कांग्रेस में वही होगा, जो गांधी परिवार यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चाहेंगी। ऐसी स्थिति रहती है तो स्वाभाविक रूप से यही कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को भले ही लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान किया जा रहा हो, लेकिन वास्तविकता इससे कोसों दूर है। हम जानते हैं कि राहुल गांधी लम्बे समय से राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस नेताओं के साथ उनका व्यवहार राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा ही था।

इसी प्रकार डॉ. मनमोहन सिंह कहने मात्र के लिए सरकार के मुखिया रहे, लेकिन आम धारणा यही बनी थी कि सरकार का सारा संचालन सोनिया गांधी ने ही किया। क्या इस बार भी कांग्रेस ऐसे ही लोकतंत्र को कायम रखेगी।

पिछले लगभग चार वर्ष से खाली पड़े कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर उठापटक जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शशि थरूर अपनी दावेदारी भी प्रकट कर चुके हैं। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी ऐसे ही संकेत दे रहे हैं।

हालांकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कौन लड़ेगा, इसकी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस के जिन नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव कराने की मांग की थी, उनमें से कोई नाम सामने नहीं आ रहा है। समूह 23 में शामिल मुकुल वासनिक के नाम की हल्की सी सुगबुगाहट जरूर सुनाई दी, लेकिन वह चुनाव लड़ेंगे, इसकी संभावना कम ही है।

कांग्रेस ने भले ही अध्यक्ष पद के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है, लेकिन जिस तरह से गांधी परिवार का दखल है उसे देखते हुए नहीं लगता कि यहां लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू होगी। वह इस पद पर अपने अनुयायी को ही बनाना पसंद करेंगे।

दरअसल कांग्रेस में युवराज राहुल गांधी ने अध्यक्ष का पद वर्ष 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस की करारी पराजय के बाद छोड़ दिया था, तब से ही सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष का प्रभार संभाले हैं। उनकी अस्वस्थता के कारण पार्टी की न तो ठीक से बैठकें हो पाती हैं और न ही कोई बड़ा निर्णय। इस बीच कांग्रेस में कई वरिष्ठ नेताओं के बगावती तेवर सामने आए। इतना ही नहीं पार्टी के अड़ियल रवैये के कारण कई वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस से नमस्ते कर ली, इसलिए अब जाकर संगठन को चुनाव

"पिछले लगभग चार वर्ष से खाली पड़े कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर उठापटक जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शशि थरूर अपनी दावेदारी भी प्रकट कर चुके हैं। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी ऐसे ही संकेत दे रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कौन लड़ेगा, इसकी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस के जिन नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव कराने की मांग की थी, उनमें से कोई नाम सामने नहीं आ रहा है।

की घोषणा करना पड़ी है।

चूंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गांधी परिवार के पक्के अनुयायी हैं, इसलिए इस पद के प्रबल दावेदार हैं, किंतु उन्हें बार-बार सोनिया गांधी और राहुल गांधी के दरबार में परिक्रमा करना पड़ रही है। अशोक गहलोत ने नई दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद भारत जोड़ो यात्रा कर रहे राहुल गांधी से भी कोच्चि में मुलाकात की।

राहुल से मिले संकेत के बाद गहलोत ने अध्यक्ष बनने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे, की बात कही है। गांधी परिवार के उम्मीदवार के रूप में देखे जाने वाले अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने का इशारा करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनावी मैदान में उतरने के अपने फैसले की घोषणा की।

पहले अशोक गहलोत ने कहा था कि वह कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के बाद भी राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में बने रहेंगे। मगर राहुल गांधी ने जब 'एक आदमी और एक पद सिद्धांत की वकालत की तो इसके बाद अशोक गहलौत के भी सुर बदल गए। वैसे वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह भी कह चुके कि गहलोत को मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए।

राहुल गांधी ने कहा था कि नए पार्टी प्रमुख को 'एक आदमी एक पद सिद्धांत का पालन करना होगा। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के बीच पार्टी नेता राहुल गांधी ने संकेत दिया कि हो सकता है कि वह पार्टी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव न लड़ें।

एक व्यक्ति, एक पद अवधारणा के मुद्दे पर राहुल गांधी ने कहा हमने उदयपुर बैठक में जो फैसला किया है वह कांग्रेस पार्टी की एक प्रतिबद्धता है। इसके तुरंत बाद अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ठीक बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कोई भी अध्यक्ष कभी मुख्यमंत्री नहीं रहा। लेकिन यहां सवाल यह है कि मुख्यमंत्री पद छोड़ने पर वह अपनी राजगद्दी किसे सौंपेंगे।

इसके लिए सचिन पायलट प्रबल दावेदार हैं, जो राहुल के साथ यात्रा में चल रहे हैं जबकि गहलौत कभी नहीं चाहेंगे कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने। उनकी इच्छा विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी या प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को मुख्यमंत्री बनाने की है।

कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 22 साल बाद चुनावी मुकाबले की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। अब यह भी लगभग तय हो चुका है कि कांग्रेस का अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया से ही बनेगा। इससे पूर्व भी वर्ष 2000 में सोनिया गांधी और जितेंद्र प्रसाद के बीच मुकाबला हुआ था। जिसमें प्रसाद को करारी शिकस्त मिली थी।

इससे पहले 1997 में सीताराम केसरी, शरद पवार और राजेश पायलट के बीच अध्यक्ष पद को लेकर मुकाबला हुआ था, जिसमें सीताराम केसरी जीते थे। अब कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष का फिर से चुनाव हो रहा है। लेकिन सवाल यह पैदा होने लगा है कि जो भी नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, वह बिना गांधी परिवार के कांग्रेस की राजनीति कर पाएगा?

रस्म अदायगी तक सीमित न रहे हिन्दी पखवाड़े का आयोजन

योगेश कुमार गोयल

भले ही आज हमारे देश में ही कुछ लोग हिन्दी के उपयोग को लेकर कभी-कभार बेवजह का विवाद खड़ा कर अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास करते दिखते हैं लेकिन हर भारतीय के लिए गर्व की बात यह है कि हिन्दी को चाहने वालों की संख्या अब दुनियाभर में लगातार बढ़ रही है। डा. फादर कामिल बुल्के ने संस्कृत को मां, हिन्दी को गृहिणी और अंग्रेजी को नौकरानी बताया था। आयरिश प्रशासक जॉन अब्राहम ग्रियर्सन को भारतीय संस्कृति और यहां के निवासियों के प्रति अगाध प्रेम था, जिन्होंने हिन्दी को संस्कृत की बेटियों में सबसे अच्छी और शिरोमणि बताया था। दूसरी ओर हमारे ही देश में कुछ लोग कुतर्क देते हैं कि भारत सरकार योग को तो 177 देशों का समर्थन दिलाने में सफल हो गई लेकिन हिन्दी के लिए 129 देशों का समर्थन भी नहीं जुटा सकी। हालांकि इस प्रकार की नकारात्मक बातों से न हिन्दी का कुछ भला होने वाला है और न ही उसका कोई बिगड़ने वाला है। ऐसे व्यक्ति हिन्दी की बढ़ती ताकत का यह सकारात्मक पक्ष बहुत चालाकी से नजरअंदाज कर देते हैं कि आज विश्वभर में करोड़ों लोग हिन्दी बोलते हैं। हिन्दी को लेकर भारतेन्दु हरिश्चंद्र ने एक बार कहा थाः-

निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।
बिन निज भाषा-ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल।।

अर्थात अपनी भाषा से ही उन्नति संभव है क्योंकि यही सारी उन्नतियों का मूलाधार है। मातृभाषा के ज्ञान के बिना हृदय की पीड़ा का निवारण संभव नहीं है। देश-विदेश के बड़े-बड़े विद्वानों ने हिन्दी भाषा के महत्व को समय-समय पर अपने शब्दों में व्यक्त किया है। पुरुषोत्तमदास टंडन मानते थे कि जीवन के छोटे से छोटे क्षेत्र में भी हिन्दी अपना दायित्व निभाने में समर्थ है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जनसम्पर्क के लिए हिन्दी को ही सबसे उपयोगी भाषा मानते थे। हिन्दी भाषा के महत्व को स्वीकारते हुए वह कहा करते थे कि सम्पूर्ण भारत के परस्पर व्यवहार के लिए ऐसी भाषा की आवश्यकता है, जिसे जनता का बड़ा भाग पहले से ही जानता-समझता है और राज व्यवहार में हिन्दी को काम में लाना देश की शीघ्र उन्नति के लिए आवश्यक है। गांधी जी कहते थे कि दिल की कोई भाषा नहीं है, दिल दिल से बातचीत करता है और राष्ट्रभाषा के बिना एक राष्ट्र गूंगा है। अमेरिका के जाने-माने चिकित्सक वॉल्टर चेनिंग का कहना था कि विदेशी भाषा का किसी स्वतंत्र राष्ट्र के राजकाज और शिक्षा की भाषा होना सांस्कृतिक दासता है। माखनलाल चतुवेर्दी हिन्दी को देश और भाषा की प्रभावशाली विरासत मानते थे जबकि राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार संस्कृत की विरासत हिन्दी को जन्म से ही मिली है। बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' का कहना था कि राष्ट्रीय एकता की कड़ी हिन्दी ही जोड़ सकती है।

"देशभर में हिन्दी पखवाड़े के अंतर्गत अनेक प्रतिष्ठानों में हिन्दी को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से कई प्रकार की गतिविधियां चलाई जा रही हैं लेकिन हिन्दी पखवाड़े के नाम पर हर साल ऐसे आयोजनों को महज रस्म अदायगी के रूप में ही देखा जाता रहा है।

महात्मा गांधी के हिन्दी प्रेम को परिभाषित करता वर्ष 1917 का एक ऐसा किस्सा सामने आता है, जब कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन के मौके पर बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रभाषा प्रचार संबंध कांफ्रैंस में अंग्रेजी में भाषण दिया था और गांधी जी ने उनका वह भाषण सुनने के पश्चात उन्हें हिन्दी का महत्व समझाते हुए कहा था कि वह ऐसा कोई कारण नहीं समझते कि हम अपने देशवासियों के साथ अपनी ही भाषा में बात न करें। गांधी जी ने कहा था कि अपने लोगों के दिलों तक हम वास्तव में अपनी ही भाषा के जरिये पहुंच सकते हैं। दरअसल हिन्दी ऐसी भाषा है, जो प्रत्येक भारतीय को वैश्विक स्तर पर सम्मान दिलाती है। बहुत सारे देशों में अब वहां की स्थानीय भाषाओं के साथ हिन्दी भी बोली जाती है। इसके अलावा दुनिया के सैंकड़ों विश्वविद्यालयों में हिन्दी पढ़ाई जाती है और यह वहां अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसंधान की भाषा भी बन चुकी है।

दुनियाभर में आज करीब 75 करोड़ व्यक्ति हिन्दी बोलते हैं और जिस प्रकार वैश्विक परिदृश्य में हिन्दी की स्वीकार्यता निरन्तर बढ़ रही है, उसे देखते हुए यह कहना असंगत नहीं होगा कि अब वह दिन ज्यादा दूर नहीं, जब हमारी राजभाषा हिन्दी चीन की राजभाषा चीनी को पछाड़कर शीर्ष पर पहुंच जाएगी। विश्वभर में हमारी हिन्दी फिल्म इंडस्ट्री 'बॉलीवुड' का नाम है, जहां हर साल करीब डेढ़ हजार फिल्में बनती हैं और ये फिल्में भारत के अलावा विदेशों में भी खूब पसंद की जाती हैं। यही कारण है कि बॉलीवुड सितारे अक्सर अपनी फिल्मों के प्रचार-प्रसार के लिए अब विदेशों में शो आयोजित करते हैं। यूएई में हिन्दी एफएम चैनल वहां के लोगों की खास पसंद हैं। जब हम ऐसे-ऐसे देशों में भी हिन्दी को भरपूर प्यार, स्नेह, सम्मान मिलता देखते हैं, जो अपनी मातृभाषाओं को लेकर बेहद संवेदनशील रहते हैं और उसे अपनी सांस्कृतिक अस्मिता से जोड़कर देखते हैं तो यह वाकई हम भारतीयों के लिए गौरवान्वित करने वाली उपलब्धि ही है। आज दुनिया का हर वह कोना, जहां भारतवंशी बसे हैं, वहां तो हिन्दी धूम मचा ही रही है। तो आइए, आज हिन्दी दिवस के अवसर पर हिन्दी भाषा और हिन्दी साहित्य को सर्वांग सुंदर बनाने का संकल्प लेकर डा. राजेन्द्र प्रसाद के इसी सपने को साकार करने का हरसंभव प्रयास करें।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं तथा 'प्रदूषण मुक्त सांसें', 'तीखे तेवर', दो टूक', 'जीव जंतुओं का अनोखा संसार', 'मौत को खुला निमंत्रण' इत्यादि कुछ चर्चित हिन्दी भाषी पुस्तकों के लेखक हैं)

वर्ष : 01, अंक : 03, नई दिल्ली, बुधवार, 12 अक्टूबर, 2022

सामान नागरिक संहिता के परिणाम

नीलम महाजन सिंह

अब नरेंद्र मोदी सरकार सामान नागरिक संहिता को प्रमाणित करने की ओर अग्रसर है। दिल्ली उच्च न्यायालय की पीठ; माननीय जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह ने पहले ही महत्वपूर्ण आदेश दिये है, जिस से देश की राजनीति पुणः गर्मा गयी है। भारत में फिलहाल संपत्ति, शादी, तलाक और उत्तराधिकार जैसे मामलों के लिए हिंदू, ईसाई, जोरेसटरीयन और मुसलमानों का अलग-अलग पर्सनल लॉ है। इस कारण एक जैसे मामलों को निपटाने में पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है। भारत में लंबे अरसे से समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर बहस होती रही है। खासकर भाजपा जोर-शोर से इस मुद्दे को उठाती रही है, लेकिन कांग्रेस व अन्य विपक्षी दल इसका विरोध करते रहे हैं। तीन तलाक (ट्रीपल तलाक) को अवैध करार कर भाजपा ने मुस्लिम महिलाओं को अपना वोट बैंक बनाने का प्रयास किया। इसका सामाजिक और धार्मिक असर तो पड़ता ही है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के प्रथम और द्वितीय काल में, जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी का अकल्पनीय विस्तार हुआ है। दो मूल उद्देश्य लागू कर दिये गये हैं। पहला; राम मंदिर निर्माण और दूसरा; कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा, उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा को नियुक्त कर, कशमीरी नेताओं के साथ समन्वय और समाधान ढूंढने का प्रयास। राह मगर अभी भी जटिल है ! राम मंदिर भूमितल का सुप्रीम कोर्ट का 2:2 का फैसला था। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई का वीटो निर्णय था। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अरविंद बोबडे ने बाबरी मस्जिद वाली भूमी को सरकार द्वारा नोटीफाई कर, वहां राम मन्दिर निर्माण का फैसला दिया। जस्टिस धनंजय वाई. चन्द्रचूड एवं जस्टिस एस.अब्दुल नाजीर ने असहमति जताई तथा असहमत फैसला दिया। इस कारण जस्टिस रंजन गोगोई का पक्ष में फैसले की निर्णयक भूमिका रही। गोगोई के राजनीतिक भूमिका पर अनेक प्रश्न चिन्ह हैं। तुरंत उन्हें राज्य सभा का सदस्य मनोनीत कर दिया गया था। फिर कश्मीर समस्या का हल काफी संवेदनशील मुद्दा है। 'एक विधान एक निशान' द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी के 'कश्मीरीयत, जमहुरियत और इंसानियत' के सिद्धांत को वास्तव मे धरातल पर उतार पाना जटिल है।

जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह ने कहा कि, 'सामान नागरिक संहिता की जरूरत लागू करने का सही वक्त आ गया है'। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि, 'आर्टिकल 44 में, जिस यूनिफार्म सिविल कोड की उम्मीद जताई गई है, अब उसे हकीकत में बदलना चाहिए'। जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह ने कहा, 'भारतीय समाज में धर्म, जाति, विवाह आदि की पारंपरिक बेड़ियां टूट रहीं हैं। युवाओं को अलग-अलग पर्सनल लॉं से उपजे विवादों के कारण शादी और तलाक के मामले में संघर्ष का सामना न करना पड़े। ऐसे में कानून लागू करने का यह सही समय है'। कोर्ट ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है। जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह की पीठ, राजस्थान की मीणा जनजाति की महिला और उसके हिंदू पति की तलाक की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। नागरिकों को विभिन्न पर्सनल लॉं में विरोधाभास के कारण संघर्ष से बचाना है। अदालत ने निर्देश दिया कि इस आदेश की जानकारी केंद्र सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के सचिव को दी जाए, ताकि वह आवश्यक कार्रवाई करें।

मौजूदा मामले में भी अलग-अलग कानून का विरोधाभास सामने आने पर हाईकोर्ट ने यह आवश्यकता समान नागरिक संहिता को कार्यान्वित करने के आदेश दिए हैं। इस जोड़े की शादी 24 जून, 2012 को हुई थी। पति ने 2 दिसंबर, 2015 को परिवार अदालत में तलाक की याचिका दायर की। महिला का पति हिंदू विवाह कानून (छल्लश्चि टं१ॽ१ अ३-1955) के मुताबिक तलाक चाहता था। लेकिन महिला का कहना है कि वह मीणा समुदाय से ताल्लुक रखती है, इसलिए उस पर 'हिंदू मैरिज एक्ट' लागू नहीं होता। बाद में फैमिली कोर्ट ने हिंदू मैरिज एक्ट-1955 का हवाला देते हुए याचिका को खारिज कर दिया। फैसले में कहा गया कि महिला राजस्थान की अधिसूचित जनजाति से है, इसलिए उस पर हिंदू विवाह कानून लागू नहीं होता। महिला के पति ने फैमिली कोर्ट के फैसले को 28 नवंबर, 2020 को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को दरकिनार करते हुए पति की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि इस तरह के मामलों के लिए ही ऐसे कानून की जरूरत है, जो सभी के लिए समान हो। कोर्ट ने यह भी कहा, उसके सामने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह पता चले कि मीणा जनजाति समुदाय के ऐसे मामलों के लिए कोई विशेष अदालत है।

> **बतौर सी.जे.आई. गोवा में हाई कोर्ट बिल्डिंग के उद्घाटन के मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा था कि गोवा के पास पहले से ही ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड है जिसकी कल्पना संविधान निर्माताओं ने की थी। 'एक देश, एक कानून' को किस प्रकार, विभिन्न जातियां, धर्म, समुदाय स्वीकार करेंगें, यह कहना काल्पनिक होगा। भारतवर्ष मे अभी तक, विभिन्नता मे एकता तो है, परंतु राजनैतिक रूप से यह कितना प्रभावी होगा, समय ही बतायेगा।**

क्या है समान नागरिक संहिता ?

संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक के द्वारा राज्यों को कई मुद्दों पर सुझाव दिए गए हैं। जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह ने इस कानून की जरूरत पर बल देते हुए कहा, संविधान के अनुच्छेद 44 में उम्मीद जताई गई है कि राज्य अपने नागरिकों के समान नागरिक संहिता की सुरक्षा करेगा। अनुच्छेद की यह भावना महज उम्मीद बनकर ही नहीं रह जाए। अनुच्छेद 44 राज्य को सही समय पर सभी धर्मों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने का निर्देश देता है। दरअसल देश में समान नागरिक संहिता का मामला पहली बार 1985 में शाहबानो केस के बाद सुर्खियों में आया।

सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के बाद शाहबानो के पूर्व पति को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। गुप्तचर विभाग ने यह सूचना दी कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से मुस्लिम समुदाय में रोष है। तब राजीव गांधी की सरकार ने संसद में विधेयक पास करा कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। तभी केरल के राज्यपाल, आरिफ मोहम्मद खान, ने लोक सभा से त्यागपत्र दिया था। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने 1985 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी एक निर्देश का हवाला देते हुए निराशा जताई कि तीन दशक बाद भी इसे गंभीरता से नहीं लिया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे ने गोवा के यूनिफॉर्म सिविल कोड की तारीफ की थी। बतौर सी.जे.आई. गोवा में हाई कोर्ट बिल्डिंग के उद्घाटन के मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा था कि गोवा के पास पहले से ही ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड है जिसकी कल्पना संविधान निर्माताओं ने की थी। 'एक देश, एक कानून' को किस प्रकार, विभिन्न जातियां, धर्म, समुदाय स्वीकार करेंगें, यह कहना काल्पनिक होगा। भारतवर्ष मे अभी तक, विभिन्नता मे एकता तो है, परंतु राजनैतिक रूप से यह कितना प्रभावी होगा, समय ही बतायेगा।

(वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनैतिक समीक्षक, पूर्व दूरदर्शन समाचार संपादक, मानवाधिकार संरक्षण अधिवक्ता व लोकोपकारक)

नीतीश ने PM बनने की खातिर लालू से किया गठबंधन : अमित शाह

प्रदीप शर्मा

बिहार के पूर्णिया में अमित शाह ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार की राजनीति स्वार्थ की राजनीति है. उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस, बीजेपी समेत कइयों को धोखा दिया है. एक दिन वह लालू का साथ छोड़कर कांग्रेस के पास चले जाएंगे. जॉर्ज के कंधे पर बैठकर उन्होंने समता पार्टी बनाई और जॉर्ज की तबीयत खराब हुई तो उन्होंने हटा दिया. शरद यादव को धोखा दिया. फिर भाजपा को पहली बार धोखा दिया, फिर जीतनराम, फिर रामविलास पासवान और फिर पीएम बनने की लालसा में बीजेपी को धोखा देकर लालू के साथ चले गए।

उन्होंने आगे कहा कि मेरे आने से लालू नीतीश की जोड़ी के पेट में दर्द हो रहा है. कह रहे हैं कि झगड़ा लगाने आए हैं. मैं झगड़ा लगाने नहीं आया. नीतीश तो लालू के साथ मिल गए. हम तो विकास और सेवा की राजनीति के पक्षधर हैं।

पीएम बनने के लिए नीतीश बाबू जो कांग्रेस विरोधी राजनीति से पैदा हुए आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिल गए हैं. सत्ता के स्वार्थ में दलबदल करके नीतीश पीएम बन सकते हैं क्या, बिहार में सरकार चल सकती है क्या? लालू भी ये समझ लें कि नीतीश आपको भी धोखा देंगे और कांग्रेस के साथ मिल जाएंगे।

अमित शाह ने मंच से कहा कि मुझे मालूम है कि आप मुझे सुन रहे हैं। मेरे भाषण में नुक्स निकाल रहे हैं। कागज पर निकाल लीजिए। बहुत सारे प्रोजेक्ट के बजट बढ़ गए हैं। अमित शाह ने नीतीश कुमार से पूछा कि हमने तो हिसाब दिया, अब आप बताइए कि आपने क्या किया है। सत्ता की कुटिल राजनीति से प्रधानमंत्री नहीं बना जा सकता। अमित शाह ने कहा धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है या नहीं। लालू-नीतीश एक बार बोल दें कि मोदी जी ने धारा 370 हटाकर अच्छा काम किया या नहीं। उनकी हिम्मत नहीं है आप तो बोलते हैं ना !

अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार गरीबों की सरकार है। हम गरीबों का सशक्तिकरण करना चाहते हैं। 50 फीसद आबादी बिहार में गरीबों की है। बिहार के घरों में 100 फीसद बिजली पहुंचाने का काम किया, गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम किया। 2 साल तक कोरोना के टीके लेने के बाद हर गरीब को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो राशन मुफ्त में देने का काम किया। हर घर में बैंक अकाउंट पहुंचाया। डायरेक्ट बेनिफिट प्लान के जरिए लोगों के खाते में पैसा पहुंचाया। अब लालू के बिचौलिए आपका हक मार नहीं सकेंगे। पूर्णिया में हवाई अड्डा बन गया है। 12 जिले के लोगों को लाभ मिलेगा। यहां से सस्ती फ्लाइट मिलेगी। इसके लिए अब पटना नहीं जाना पड़ेगा।

> **अमित शाह ने मंच से कहा कि अब ना नीतीश कुमार की पार्टी आएगी, ना लालू की पार्टी आएगी। अब सीमांचल के हिस्से में मोदी जी का कमल खिलेगा। 2024 में महागठबंधन का सूपड़ा साफ हो जाएगा। नीतीश कुमार की एक ही नीति केवल कुर्सी रहनी चाहिए। नीतीश कुमार दल बदल कर जो धोखा दे रहे हैं, यह धोखा पीएम मोदी के साथ नहीं है। यह धोखा बिहार की जनता के साथ है।**

महागठबंधन सरकार पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार ने लालू यादव के साथ जाकर जंगलराज का नजरिया स्पष्ट कर दिया है। जिस दिन से महागठबंधन की सरकार बनी है, उसी दिन से कानून-व्यवस्था चरमरा गई। नीतीश कुमार ने कहा हमारे साथ षड्यंत्र किया जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा था कि बिहार में जनता राज है, षड्यंत्र किया जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार आप भूल रहे हैं कि आप तो षड्यंत्र करने वालों के साथ ही बैठे हैं।

अमित शाह ने मंच से कहा कि अब ना नीतीश कुमार की पार्टी आएगी, ना लालू की पार्टी आएगी। अब सीमांचल के हिस्से में मोदी जी का कमल खिलेगा। 2024 में महागठबंधन का सूपड़ा साफ हो जाएगा। नीतीश कुमार की एक ही नीति केवल कुर्सी रहनी चाहिए। अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार दल बदल कर जो धोखा दे रहे हैं, यह धोखा पीएम मोदी के साथ नहीं है। यह धोखा बिहार की जनता के साथ है।

अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए नीतीश बाबू ने जो एंटी कांग्रेस राजनीति से जन्म लिया और आरजेडी की गोदी में बैठने का काम किया है। अमित शाह ने मंच से नारे लगवाते हुए कहा कि क्या इस तरीके से नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन सकते हैं? अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार ने एक के बाद एक कई लोगों के साथ यही किया। नीतीश ने तो लालू के साथ भी कपट किया। अमित शाह ने मंच ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव को चेतावनी देते हुए कहा कि लालू जी संभल कर रहिएगा, नीतीश कुमार आपको भी धोखा देकर कांग्रेस के साथ मिल जाएंगे। अमित शाह ने कहा कि बिहार की भूमि परिवर्तन का केंद्र रही है। इंदिरा जी के इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन बिहार की भूमि और सीमांचल से ही शुरू हुआ है। नीतीश कुमार और लालू के खिलाफ बिगुल फूंकने का काम भी हम यहीं से करेंगे।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बिहार के दो दिवसीय दौरे पर हैं. बिहार में सरकार से बाहर होने के बाद बीजेपी के किसी वरिष्ठ नेता का ये पहला बिहार दौरा है. किशनगंज में पार्टी विधायकों सांसदों के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद पार्टी की बिहार इकाई की कोर कमिटी की बैठक में भी शामिल होंगे।

राजनीतिक तरकस
देश का सबसे तेज साप्ताहिक
राष्ट्रीय विचार, सटीक समाचार
5
वर्ष वर्ष : 01 , अंक : 03, नई दिल्ली, बुधवार, 12 अक्टूबर, 2022

संकल्प से सिद्धि मंत्र के साथ राष्ट्र सेवा के सौ माह

'दिल्ली का पंजाबी खाना खा-खा कर तुम मोटे हो गए हो, गुजरात लौट जाओ'

ये वाजपेयी जी का अंदाज था, बाक़ी जो हुआ वो इतिहास है। 7 अक्टूबर 2001 में पहली बार नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

इंदिरा हारी, राजीव हारे, राव हारे, वाजपेयी भी हारे। लेकिन 21 साल के इस सफ़र में मोदी के हिस्से एक भी हार नहीं आया।

आप सरकार की नीतियों,फ़ैसलों से सहमत असहमत हो सकते हैं। मगर इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि चुनावी प्रबंधन में मोदी का कोई सानी नहीं है। संगठन, प्रशासन और भाषण में नरेंद्र मोदी का कोई जोड़ नहीं है। कुछ ऐसी बातें हैं जो उन्हें चुनाव दर चुनाव जीत दिलाते हैं।

प्रधानमंत्री के रूप में 100 महीने पूरे करने वाले नरेंद्र मोदी के बीते 8 वर्ष में लिए गए सैकड़ों निर्णायक-दूरगामी निर्णय 2047 के स्वर्णिम नए भारत के लिए चल रही अमृत यात्रा का आधारस्तंभ बन गए हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में लगभग 13 वर्ष तक अपनी राजनीति का सिक्का चलाने के बाद 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इस महीने मोदी ने अपनी सत्ता के 100 माह के पूरे कर लिए। ऐसे में यह देखना लाजिमी हो जाता है कि आखिर वह कौन सी चीज है जो मोदी को अपने विरोधियों से अलग एक ऐसी छवि प्रदान करती है जो उनके विरोधी लाख चाहकर भी इस वक्त हासिल नहीं कर पा रहे हैं। हमें इस बातों को समझने के लिए मोदी सरकार की योजनाओं नीतियों और कार्य प्रणालियों पर नजर डालनी होगी।

आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से सिद्धि के मंत्र उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ ही भारत को शिखर पर ले जाने की उनकी जिजीविषा को प्रदर्शित करता है। मोदी के इस विजन ने बच्चों से लेकर के युवाओं तक के मन में एक नई आस पैदा की है। मोदी ने बीते 8 वर्ष की विकास यात्रा को आधार स्तंभ बनाकर आजादी के 100वें वर्ष यानी 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100 महीने 100वें वर्ष के नए भारत का आधार बन गए हैं।

भारत अपने शताब्दी वर्ष के संकल्प के साथ अमृत यात्रा प्रारंभ कर चुका है। आत्मनिर्भरता और आजादी को एकदूसरे का पूरक कहा जाता है. जो देश जितना आत्मनिर्भर होगा, वो उतना ही सशक्त है। इसलिए आज का भारत, बल और बदलाव दोनों को साथ लेकर चल रहा है। एक निश्चित कालखंड में भारत को विकसित बनाने का संकल्प यूं ही नहीं है। विकास की नई परिभाषा ही अमृत काल का आधार बनी है।

राष्ट्रवाद को प्रेरणा, अंत्योदय को दर्शन और सुशासन को मंत्र बनाकर, देश को नई ऊंचाईयों पर ले जाने और निरंतर प्रगति के

पथ पर अग्रसर रखने की सोच के साथ पहली बार किसी केंद्र सरकार ने समयबद्ध तरीके से अंतिम छोर तक विकास की पहुंच सुनिश्चित कर विकसित भारत की बुनियाद रख दी है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली में लोगों की जरूरत को समझना सबसे महत्वपूर्ण है। वे सरकार या राजनीति में भी कोई निर्णय लेने से पहले सीधे लोगों की सोच के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। जब इस तरह का अध्ययन पूरा हो जाता है तभी वे आगे की रणनीति पर काम कर उसे साकार करते हैं। उन्होंने सदैव ऐसे विकास की सोच को आगे बढ़ाया है जो सर्वांगीण-सर्वसमावेशी-सर्वस्पर्शी हो। विकासवाद आज के भारत की नीति-रीति बन गई हैं। यहां हम कुछ ऐसे निर्णयों का जिक्र कर रहे हैं जो नए भारत की अमृत यात्रा का आधार बन गए हैं और अमृत काल के संकल्प को साकार करने का विकासरूपी संस्कार।

अटल सरकार ने बजट का समय बदला तो प्रधानमंत्री मोदी ने बजट को एक महीने पहले किया ताकि विकास की गति को एक महीने पहले दौड़ाया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं, 'अब हमने बजट एक महीना पहले किया है. एक महीना पहले करने का मतलब है मुझे देश की आर्थिक व्यवस्था को एक महीना पहले दौड़ाना है। हम देखते हैं, खास करके इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए ये समय बहुत मूल्यवान है क्योंकि हमारे यहां अप्रैल में बजट लागू होता है और उसके बाद अगर हम चर्चा शुरू करेंगे तो उसमें मई महीना निकल जाता है. मई एंड से हमारे देश में बारिश शुरू हो जाती है और इन्फ्रास्ट्रक्चर के सारे काम तीन महीने लटक जाते हैं। ऐसी स्थिति में 1 अप्रैल से ही काम शुरू जाए तो हमें अप्रैल-मई-जून, इन्फ्रास्ट्रक्चर काम के लिए बहुत समय मिल जाता है; जुलाई-अगस्त-सितम्बर बारिश के दिन होते हैं; फिर हम तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं। समय का उत्तम उपयोग करने के लिए ये बजट हम एक महीना पहले करके आगे बढ़ रहे हैं।

इतना ही नहीं, किसानों की आय दोगुनी करने का एक विराट लक्ष्य लिया गया और इसके लिए सरकार ने बुवाई से पहले, बुवाई के दौरान और बुवाई के बाद के हर चरणों में किसानों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाईं। कभी कुपोषण को खत्म करने के लिए ऐसे प्रयास नहीं हुए, लेकिन पोषण अब राष्ट्र का मिशन बन गया है और सही पोषण से देश रोशन की आवाज बुलंद हो रही है। दर्जन भर से अधिक मंत्रालय इसके लिए एक साथ प्रयास में जुटे हैं। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ ने लिंगानुपात में लड़कियों की संख्या बढ़ा दी है तो हर घर नल से जल का भागीरथी सपना साकार हो रहा है। जबकि आजादी के इतने लंबे अरसे तक 15 करोड़ ग्रामीण घरों में पीने को स्वच्छ पानी भी उपलब्ध नहीं था।

कोविड की आपदा के समय को अवसर में बनाकर भारत ने पीपीई किट, एन-95 मास्क जैसे उत्पाद जो देश में न के बराबर होते थे, भारत उसका निर्यातक बन गया है. स्वास्थ्य क्षेत्र में जनक्रांति की शुरुआत हो चुकी है और यूनिवर्सल हेल्थकेयर आज की हकीकत बन रही है। आयुष्मान भारत योजना, डिजिटल स्वास्थ्य का ढांचा अब स्वास्थ्य सुविधाओं को सहज बना रहा है। जनऔषधि योजना से सस्ती दवाई की पहुंच हो या फिर वैक्सीन से जुड़े प्रयास असम में बोगीबिल ब्रिज हो या कश्मीर में चिनाब ब्रिज हल्दिया से वाराणसी जलमार्ग की शुरुआत हो या सभी परियोजनाओं को जोड़कर पीएम-गतिशक्ति की शुरुआत, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और स्वदेशी निर्माण व खरीद को बढ़ावा देना, उरी-बालाकोट से दुनिया को नए भारत की शक्ति का अहसास कराना। आज भारत की नीति-रीति बन गई है।

स्टार्टअप से यूनिकॉर्न की यात्रा हो या हर गरीब तक स्वच्छ ईंधन पहुंचाने वाली उज्ज्वला योजना, हर नागरिक को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने वाली जन-धन योजना हो या या जनजातीय कल्याण के लिए समग्रता में प्रयास, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाना हो या फिर सवर्ण आरक्षण। उपेक्षित नायकों को सम्मान दिलाना हो या विदेश नीति को मजबूत कर भारतीय पासपोर्ट की ताकत को बढ़ाना, एक देश-एक राशन कार्ड के साथ-साथ एक देश-एक व्यवस्था की अनगिनत पहल, अनुच्छेद-370 से आजादी हो या दिव्यांग जनों के लिए सुगम्य भारत का निर्माण, पीएम आवास, मुद्रा योजना से स्वरोजगार, स्वनिधि से रेहड़ी-पटरी वालों का स्वावलंबन, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति- हैकॉथन से नई सोच का विकास, आकांक्षी जिलों के विकास पर फोकस,जनसहभागिता, जीवन प्रमाणन, हर घर बिजली, बीमा और पेंशन योजना, डीबीटी, श्रम सुधार-ई श्रम पोर्टल, महिला सुरक्षा- मातृत्व अवकाश, स्थायी कमीशन, लिंगानुपात में सुधार, कानूनी सुरक्षा जैसी तमाम पहल तीन तलाक से मुक्ति, खेल का नया ईको-सिस्टम- खेलो इंडिया, टॉप्स, तीन ओलंपिक की सोच पर 2016 में ही कमेटी बनाकर की गई पहल ताकि खेलों को लेकर समाज की बदली सोच. कौशल विकास की नई शुरुआत, सड़क-राजमार्ग- नेशनल हाईवे- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आदि. उड़ान योजना टेकेड यानी तकनीक से विकास को नई उड़ान. जीएसटी- एक देश एक टैक्स, यूपीआई लेनदेन- 40 प्रतिशत अकेले भारत में होना, प्रगति प्लेटफॉर्म, लंबित परियोजनाएं जो हुई साकार- जैसे सरयू नहर, कोसी, कोल्लम बाईपास, अटल सुरंग, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे- नदी जोड़ो परियोजना आदि. पुराने कानूनों के जंजाल से मुक्ति से सुगम कार्यनीति, इनोवेशन की नई सोच- इनोवेशन इंडेक्स में मजबूत भारत, पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत का पश्चिम की तरह विकास, सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण- विरासत पर गर्व- मूर्तियां वापस लाना, धरोहरो की संख्या बढ़ना. राम मंदिर- 499 वर्ष पुराना विवाद खत्म- सांप्रदायिक सौहार्द के साथ, काशी कॉरीडोर का निर्माण, केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण, डेरा बाबा नानक-करतारपुर कॉरीडोर, सोमनाथ का पुनरोद्धार, हाइड्रोजन मिशन, मेक इन इंडिया, नीति आयोग का गठन, सेंट्रल विस्टा-संसद भवन, इंटरनेशल योग दिवस, स्व-प्रमाणन, निचले ग्रेड की नौकरियों में इंटरव्यू खत्म, पद्म पुरस्कार बना जनता का पद्म, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस आत्मनिर्भरता बना आंदोलन- वोकल फॉर लोकल का मंत्र अब हर भारतीय के मन-मस्तिष्क में छाया। और अब आखिर में अमृत यात्रा यानी शत-प्रतिशत लोगों तक लाभ पंहुचाने के लक्ष्य के साथ विकसित भारत का सपना साकार करने की दिशा में बढ़ने के संकल्प के साथ एक यात्रा।

पांच दशक का सार्वजनिक जीवन और 20 वर्ष से अधिक शासन में 'सेवक' बनकर अपनी निष्ठा और राष्ट्र-समाज को नई दिशा देने की सोच के साथ आगे ले जाने की दृढ़ इच्छाशक्ति ही किसी नेतृत्वकर्ता को जन-जन का सम्मान दिलाती है। ऐसे ही व्यक्तित्व के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2022 को बतौर प्रधानमंत्री 100 महीने पूरे करने का अपने नाम नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वे भले ही 100 महीने पूरे करने वाले देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए हैं और गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में एक नई लकीर खींच दी है, लेकिन उससे बड़ा कीर्तिमान उनके द्वारा लिए गए निर्णय हैं जिसने देश के विकास की धारा को बदल दिया है। अगर आज भारत अमृत यात्रा के साथ एक निश्चित कालखंड यानी 2047 में भारत को विकसित बनाने का विराट लक्ष्य लेकर चल पड़ा है तो उसका बड़ा आधार बीते 100 महीने में लिए गए प्रधानमंत्री मोदी के निर्णय ही हैं। राजनीति में तमाम आलोचनाओं के बावजूद अपनी नीति में 'राष्ट्र सर्वोपरि-राष्ट्र प्रथम' जैसे विचारों को प्रवाहमान बना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नित नए और निर्णायक फैसलों से नए भारत की आधारशिला तैयार कर चुके हैं और भविष्य के भारत का स्वर्णिम इतिहास रचने को आतुर हैं।

लखीमपुर खीरी कांड - राक्षसों पर अंकुश के लिए कठोर सजा जरूरी !

दीपक कुमार त्यागी

जिस गौरवशाली संस्कृति वाले महान भारत में मातृशक्ति स्त्री को आदिकाल से ही बेहद पूजनीय माना जाता रहा है, आज वहां पर मातृशक्ति के प्रति आयेदिन बेहद जघन्य श्रेणी के अपराध घटित होना एक साधारण घटना व बेहद आम बात बनती जा रही है, जो ठीक नहीं है। आज हमारे सभ्य समाज के लिए बेहद चिंताजनक बात यह है कि हमारे प्यारे देश भारत में वर्ष दर वर्ष महिलाओं के प्रति घटित होने वाले अपराध कम होने की जगह बहुत तेजी के साथ बढ़ते ही जा रहे हैं। जबकि अब तो समाज के अधिकांश व्यक्ति यह बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर की पृथ्वी पर सबसे बेहतरीन व खूबसूरत रचना मातृशक्ति के रूप में ही है, जो कि इंसान को जन्म देने की शक्ति भी रखती है और मां बहन पत्नी व बेटी जैसे बेहद अनमोल रिश्ते को भी देती है। हालांकि आज देश के कुछ बेहद व्यवसायिक लोगों के द्वारा अपने हितों को साधने के चक्कर में स्त्री को बाजारवाद के इस दौर में एक वस्तु मात्र बनाकर रखने का बेहद शर्मनाक मानसिक दिवालियेपन का गंदा खेल चल रहा है, जिसको हमें समय रहते रोकना होगा। वहीं देश में आज आधी अधूरी पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण के चलते व कुछ लोगों की बेहद ओछी सोच ने महिलाओं को उपभोग का एक खिलोना मात्र बनाने का दुस्साहस किया है, जिसे प्रभावित होकर कुछ लोग उनके मान सम्मान से आयेदिन खिलवाड़ करने का निंदनीय अक्षम्य अपराध करने का प्रयास करते हैं, जो कि हमारे सभ्य समाज के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है और एक बहुत बड़ा अपराध है। वैसे भी जिस तरह से आज देश मे.बेहद सुलभता से उपलब्ध इंटरनेट ने दुनिया को छोटे से मोबाइल में सिमेटने का कार्य किया है, उससे आम लोगों को भी अच्छा व बुरा सब कुछ बहुत ही आसानी से मोबाइल पर देखने को मिल रहा है, जिसका कुछ नादान लोगों के द्वारा बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसके चलते भी बहुत तेजी के साथ कुछ लोग संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। वैसे धरातल पर निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो भारतीय समाज में नैतिक मूल्यों में पिछले कुछ वर्षों से बहुत ही तेजी से गिरावट आती जा रही है, नैतिक पतन के चलते ही आज देश में बच्चों, बच्चियों, नोजवानों, महिलाओं व बुजुर्गों के साथ भी आयेदिन लोगों के दिलोदिमाग को झकझोर देने वाली बेहद शर्मनाक कृत्य वाली आपराधिक घटनाएं घटित होती रहती हैं, रोजाना ही देश के किसी ना किसी भाग से अपराध की बेहद चिंतित करने वाली खबरें आती रहती हैं। वैसा ही एक बेहद झकझोर देने वाला समाचार हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद से भी आया है।

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद के निघासन थाना इलाके के तमोलीन पुरवा गांव में बुधवार 14 सितंबर को दो सगी नाबालिग बहनों के शव गांव के बाहर खेत में पेड़ पर संदिग्ध परिस्थितियों में लटके हुए मिलने से पूरे इलाके में सनसनी मच गयी थी। सूत्रों के अनुसार इस घटना के संदर्भ में बुधवार की शाम तकरीबन 5 बजकर 40 मिनट पर पुलिस को डायल 112 पर सूचना मिलने के बाद से स्थानीय जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक जबरदस्त हड़कंप मच गया था। चंद मिनटों में ही हर तरफ सोशल मीडिया के बेहद ताकतवर हो चुके प्लेटफॉर्म ने लोगों को जघन्य अपराध की इस शर्मनाक घटना से अवगत करवा दिया था। जिसके बाद हर घटना की तरह ही ट्विटर पर आरोप प्रत्यारोप व बचाव करने के लिए ट्वीट-ट्वीट खेलने वाले बयानवीरों की बाढ़ आ गयी थी, देश के कुछ दिग्गज राजनेता भी ट्विटर के इस खेल में शामिल थे, उनमें कोई तो उत्तर प्रदेश सरकार को जमकर कोस कर नाबालिग लड़कियों की लाशों पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक रहा था, वहीं कोई उत्तर प्रदेश सरकार व पुलिस के बचाव में अपना पक्ष रख रहा था। खैर जो भी हर घटना की तरह ही इस घटना पर भी देश में भरपूर राजनीति लंबे समय तक चलती रहेगी, पीड़ित पक्ष व अपराधियों की जाति व धर्म को विभिन्न तरह से निशाना बनाकर चर्चा चलती रहेगी, राजनेताओं के राजनीतिक पर्यटन के साथ-साथ संवेदना व्यक्त करने के लिए पीड़ित पक्ष के घर के दौरे भी शुरू हो जायेंगे, वह पीड़ित पक्ष के सामने अपने सच्चे व घड़ियाली आंसू जमकर बहाएंगे, सरकार व प्रशासन राजनेताओं के उस पर्यटन को कानून व्यवस्था खराब हो जाने का हवाला देकर रोकने का कार्य करेगी, फिर रोके जाने वाले राजनेताओं के दलों के भक्तों का सड़कों पर जमकर हंगामा बरपेगा, क्योंकि भाई उनको तो केवल अपनी राजनीति चमकानी है, शायद ही किसी राजनेता को वास्तव में परिवार के दुःख से सरोकार हो। प्रशासन के द्वारा परिवार को सार्वजनिक रूप से बोलने से रोका जायेगा, उचित मुआवजा धनराशि देकर जख्मों पर अलग ही तरह का मरहम लगाया जायेगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या तारीख पर तारीख के बाद मृतक बच्चियों के अपराधियों को जल्द कठोर से कठोर सजा दिलवाने का कार्य भी समय रहते हो पायेगा, क्या देश में अपराधियों के हौसले पस्त करने के लिए पीड़ित परिवार को समय से न्याय मिल पायेगा।

> “ देश-दुनिया के किसी भी हिस्से में सभी प्रकार के जघन्य अपराधों में विशेषकर की अपहरण, हत्या, बलात्कार आदि में लोगों को अपनी बेहद जहरीली जातिवाद, धार्मिक सोच से दूर रखते हुए व राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से इतर रखते हुए, न्याय के लिए कार्य करना ही होगा, वहीं इस तरह की आये दिन होने वाली हैवानियत को रोकने के लिए पीड़ित पक्ष को जल्द से जल्द न्याय दिलवाने की नियमित परंपरा शासन-प्रशासन को शुरू करनी ही होगी और ऐसे जघन्य अपराधों के गुनहगारों को देश दुनिया में नजीर बनने वाली बेहद कठोर सजा दिलवाने का प्रावधान करना होगा, जिससे कि भविष्य में फिर कोई राक्षस किसी और के साथ ऐसी पाशविक-बर्बरता करने का दुस्साहस ना कर पाए, तब ही देश में भविष्य में नियम-कायदे व कानून का राज स्थापित होकर के सभ्य समाज को एक भयमुक्त वातावरण मिल सकता है।

देश की राजधानी दिल्ली से मात्र 465 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद के निघासन इलाके के तमोलीन पुरवा गांव में जब से दो नाबालिग बच्चियों के शव पेड़ पर झूलते हुए मिले हैं, उसके बाद एकबार फिर इस नृशंस हत्याकांड ने हम सभी देशवासियों को बुरी तरह से झकझोर कर इंसानियत को शर्मसार करने का कार्य किया है। इस हैवानियत भरे मामले पर सभ्य समाज के सभी वर्गों के लोगों में बहुत गुस्सा देखा जा रहा है। घटना के बाद क्षेत्र के लोग व परिजन पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाकर के सड़क जाम करके, विरोध प्रदर्शन करके व विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जल्द न्याय के लिए मुहिम चलाकर अपना आक्रोश व्यक्त करने कार्य कर रहे हैं। वैसे पुलिस ने इस मामले पर तत्परता दिखाते हुए 24 घंटे के अंदर ही खुलासा करते हुए, सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान छोटू, जुनैद, सोहेल, हाफिजुल, करीमुद्दीन और आरिफ के रूप में हुई है। लेकिन फिर भी क्षेत्र के आम लोगों में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त हैं, लोग यह सोचकर हैरान व परेशान है कि आखिर देश में बार-बार दरिंदों की हैवानियत का बच्चियां क्यों शिकार बनती हैं। आज सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों में छोटे बच्चों व बच्चियों के साथ आयेदिन बर्बरता, बलात्कार और हत्या जैसी गंभीर घटनाएं होना बेहद आम होता जा रहा है, जिन्होंने हमारे सभ्य समाज को झकझोर कर रख दिया है। देश में घटित इस तरह की शर्मनाक घटनाओं ने एक बार फिर से कुछ राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों के इंसान होने पर प्रश्नचिन्ह लगाकर यह बता दिया है कि देश में आज भी इंसान व इंसानियत के दुश्मन बहुत सारे घातक राक्षस जिंदा हैं। इस मसले पर परिजनों व लोगों की मांग है कि पुलिस इस मसले की जल्द से जल्द जांच करे और शासन-प्रशासन फास्टट्रैक कोर्ट में जल्द से जल्द इस मसले का निर्णय करावा कर आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी देने का कार्य करे।

लेकिन आज सोचने वाली बात यह है कि 21वीं सदी के भारत में हम किस तरह के संस्कार विहीन, असभ्य, बर्बर, जाहिल समाज की ओर बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें कुछ लोगों के मन में नियम, कायदे, कानून का कोई भय या सम्मान ही नहीं बचा है। आज भी देश में राक्षसी प्रवृत्ति के कुछ लोग पूरी तरह से बेखौफ होकर अपराध कर रहे हैं, इनको अपराध करने से रोकने के लिए पुलिस व्यवस्था नाकाफी साबित हो रही है। वैसे सोचने वाली बात यह है कि जिस भारत में वैसे तो मातृशक्ति की पूजा होती है, जिस देश में कहा जाता है कि जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं और जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं होती है, उनका मान-सम्मान नहीं होता है, वहाँ पर किये गये समस्त अच्छे कर्म भी निष्फल साबित हो जाते हैं। लेकिन बेहद अफसोस की बात यह है कि उसी देश में आयेदिन मातृशक्ति के साथ ऐसे जघन्य अपराध घटित हो रहे हैं। एक तरफ तो भारत सरकार 'बेटी बचाओ बेटी पढाओ' का नारा बुलंद कर रही है, लेकिन सच यह है कि भारत में मातृशक्ति के प्रति बढ़ते अपराधों को देखकर लगता है कि देश में यह सब एक ढोंग मात्र है। वैसे आज के समय में विचारणीय तथ्य यह है कि हम लोग इन राक्षसों से अपने बच्चों व बच्चियों की इज्जत आबरू और जिंदगी की हिफाजत आखिरकार कैसे करें, देश में शासन-प्रशासन व हमारे सामने यह एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी है। वैसे हमको भी देश में अगर इस तरह के अपराध को कम करना है तो किसी अन्य के साथ होने वाली बर्बरता पूर्ण घटना को केवल एक अपराध मानकर चुपचाप आंख मूंदकर घर में नहीं बैठ जाना है, हम सभी को जागरूक रहकर बिना किसी के कहें तत्काल ही अपने-अपने हिस्से के दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। आज हम सभी को यह समझना होगा कि अपराधी का कोई जाति व धर्म नहीं होता है, वह केवल इंसान व इंसानियत का दुश्मन अपराधी होता है। देश-दुनिया के किसी भी हिस्से में सभी प्रकार के जघन्य अपराधों में विशेषकर की अपहरण, हत्या, बलात्कार आदि में लोगों को अपनी बेहद जहरीली जातिवाद, धार्मिक सोच से दूर रखते हुए व राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से इतर रखते हुए, न्याय के लिए कार्य करना ही होगा, वहीं इस तरह की आये दिन होने वाली हैवानियत को रोकने के लिए पीड़ित पक्ष को जल्द से जल्द न्याय दिलवाने की नियमित परंपरा शासन-प्रशासन को शुरू करनी ही होगी और ऐसे जघन्य अपराधों के गुनहगारों को देश दुनिया में नजीर बनने वाली बेहद कठोर सजा दिलवाने का प्रावधान करना होगा, जिससे कि भविष्य में फिर कोई राक्षस किसी और के साथ ऐसी पाशविक-बर्बरता करने का दुस्साहस ना कर पाए, तब ही देश में भविष्य में नियम-कायदे व कानून का राज स्थापित होकर के सभ्य समाज को एक भयमुक्त वातावरण मिल सकता है।

आरिफ से विजयन टक्कर न लें

डॉ. वेदप्रताप वैदिक

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को कल एक पत्रकार-परिषद बुलानी पड़ी। क्या आपने कभी सुना है कि किसी राज्यपाल ने कभी पत्रकार-परिषद आयोजित की है? राज्यपाल को पत्रकार-परिषद आयोजित करनी पड़ी है, यही तथ्य यह सिद्ध कर रहा है कि उस प्रदेश की सरकार कोई ऐसा काम कर रही है, जो आपत्तिजनक है और जिसका पता उस प्रदेश की जनता को चलना चाहिए। केरल की सरकार कौन-कौन से काम करने पर अड़ी हुई है। उसका पहला काम तो यही है कि वह अपने विश्वविद्यालयों में अपने मनपसंद के उप-कुलपति नियुक्त करने पर आमादा है। मुख्यमंत्री के साथ काम कर रहे एक भारी-भरकम नौकरशाह की पत्नी को चयन-समिति ने एक विश्वविद्यालय का उप-कुलपति चयन कर लिया। चार अन्य उम्मीदवार, जो उससे भी अधिक योग्य और अनुभवी थे, उन्हें रद्द करके इंटरव्यू में उस महिला को पहला स्थान दे दिया गया। इसी प्रकार कई अन्य विश्वविद्यालयों में उप-कुलपति पद के उम्मीदवारों की योग्यता के मानदंडों में सबसे बड़ा मानदंड यह माना जाता है कि वह सत्तारुढ़ पार्टी, माकपा, के कितना नजदीक है। इसके अलावा पार्टी-कामरेडों को नौकरशाही में भरवाया जा रहा है। उन्हें मंत्रियों और अफसरों का पीए या ओएसडी आदि बनाकर नियुक्ति दे दी जाती है ताकि दो साल की नौकरी के बाद वे जीवन भर पेंशन पाते रहें। पार्टी-कॉमरेडों को अपराधों की सजा न मिले, इसलिए उन्हें सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर भी बिठाया जा रहा है। जैसे मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन ने के.के. रागेश को अपने निजी स्टाफ में नियुक्ति दे दी है ताकि पुलिस उसे गिरफ्तार न कर सके। इस व्यक्ति ने 2019 में कन्नूर में आयोजित हिस्ट्री कांग्रेस के अधिवेशन में राज्यपाल आरिफ खान के विरुद्ध अत्यंत आपत्तिजनक व्यवहार किया था। उस अधिवेशन में राज्यपाल के भाषण में हंगामा मचानेवालों और उनके सुरक्षाकर्मियों के साथ मार-पीट करनेवाले दोषियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। राज्यपाल को पूर्णरूपेण शक्तिहीन बनाने के लिए केरल विधानसभा में दो विधेयक

भी पारित कर लिए गए हैं। एक तो उप-कुलपतियों की नियुक्ति का अधिकार उप-राज्यपाल से छीन लिया गया है और दूसरा लोकपाल के भ्रष्टाचार-विरोधी अधिकारों को कमजोर कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है लेकिन क्या वे यह नहीं जानते कि राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना वे दोनों विधेयक कानून नहीं बन सकते। उन्हें पता होना चाहिए कि राज्यपालों को अपनी प्रांतीय सरकारों पर जितने अधिकार प्राप्त हैं, उतने राष्ट्रपति को अपनी केंद्र सरकार पर भी नहीं हैं। आरिफ खान को डराना आसान नहीं है। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री राजीव गांधी को टक्कर दे सकता है, वह क्या किसी मुख्यमंत्री से डरेगा?

शेष पृष्ठ

राजनीतिक तरकस
देश का सबसे तेज साप्ताहिक
राष्ट्रीय विचार, सटीक समाचार
वर्ष : 01 , अंक : 03, नई दिल्ली, बुधवार, 12 अक्टूबर, 2022

अब एम्स का नाम बदलने की कवायद शुरू

सवांददाता

अंग्रेजी के महान नाटककार विलियम शेक्सपियर भले ही कह गए हों कि नाम में क्या रखा है, पर कुछ नामों की तो बात ही अलग होती है। वे नाम सम्मान और आदर के लायक होते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) भी इसी तरह का एक स्थापित नाम है। एम्स यानी देश भर के मरीजों का भरोसा और विश्वास। यहां पर देशभर से हर रोज सैकड़ों रोगी और उनके संबंधी इस विश्वास के साथ आते हैं कि वे यहां से सेहतमंद होकर ही घर लौटेंगे। एम्स भी उनके भरोसे पर खरा उतरने की हरचंद कोशिश करता है। यहां के डॉक्टर, नर्स और बाकी स्टाफ हरेक रोगी को स्वस्थ करने के लिए अपनी जान लगा देते हैं। अब एम्स का नाम बदलने की कवायद शुरू हो गई है। सन 1956 में स्थापित एम्स के नाम को बदलने की वैसे तो कोई जरूरत तो नहीं है। एम्स के डॉक्टरों का भी मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एम्स के डॉक्टरों का कहना है जब दुनिया भर में आक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी ने सदियों से अपने नाम नहीं बदले तो एम्स को उसकी पहचान से क्यों अलग किया जाए? बात तो ठीक ही है। भारत में आईआईटी, आईएमए और एम्स शिक्षा के क्षेत्र में बेहद प्रतिष्ठित नाम हैं। इनकी सारी दुनिया में अलग पहचान होती है। एम्स में एमबीबीएस, एमएस, एमडी वगैरह कोर्सो में दाखिला पाने के लिए देश भर के सबसे मेधावी बच्चे हर वर्ष प्रयास करते रहते हैं। वे आगे चलकर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डाक्टर के रूप में भी जाने जाते हैं। एम्स अपने यहां पढ़े विद्यार्थियों को लगातार शोध करने और मानवीय बने रहने के लिए प्रशिक्षित करता रहता है। यहां के डाक्टरों में मानव सेवा का गजब का जज्बा देखने को मिलता है। विश्व विख्यात लेखक और मोटिवेशन गुरु डॉ.दीपक चोपड़ा, शिकागो यूनिवर्सिटी के पैथोलिजी विभाग के प्रोफेसर डॉ. विनय कुमार, गंगा राम अस्पताल के मशहूर लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉ. अरविंदर सिंह सोईन, एम्स के मौजूदा डायरेक्टर डॉ.रणदीप गुलेरिया, ईएनटी विशेषज्ञ डॉ.रमेश डेका, डॉ. पी.वेणुगोपाल, डॉ. सिद्दार्थ तानचुंग, यूरोलोजिस्ट डॉ. राजीव सूद जैसे सैकड़ों चोटी के डाक्टरों ने एम्स में ही शिक्षा ग्रहण की और फिर यहाँ बरसों सेवाएं भी दीं। डॉ. राजीव सूद ने कुछ सालों तक एम्स में सेवा देने के बाद राजधानी के राममनोहर लोहिया अस्पताल (आरएमएल) को ज्वाइन किया और फिर वे इसके डीन भी रहे। वे कहते हैं कि एम्स की तासीर में ही सेवा भाव है। जो एक बार एम्स रह लिया वह फिर मानव सेवा के प्रति समर्पित रहेगा ही। इधर डॉ. जीवन सिंह तितियाल, प्रोफेसर प्रदीप वेंकटेश, प्रो डॉ. राजवर्धन आजाद, प्रोफेसर तरुण दादा, प्रोफेसर विनोद अग्रवाल जैसे बेहतरीन नेत्र चिकित्सक हैं। इन्हें आप संसार के सबसे कुशल डाक्टरों की श्रेणी में रख सकते हैं। इन सब डाक्टरों की देखरेख में ही देश के नए डाक्टर तैयार होते हैं। आपको एम्स में देश के कोने-कोने से आए हजारों रोगियों का इलाज होता मिलेगा। यहां पर भिखारी से लेकर भारत सरकार का बड़े से बड़ा बाबू भी लाइन में मिलेगा। एम्स के डाक्टर किसी के साथ उनके पद या आर्थिक आधार पर भेदभाव भी नहीं करते। यहां पर सुबह-शाम रोगियों का आना-जाना इस बात की गवाही है कि देश को एम्स पर भरोसा है। एम्स भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री और गांधी

“ एम्स की स्थापना के 66 सालों के बाद इसका नाम बदलने का कोई औचित्य समझ नहीं आता। इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। एम्स को तो सिर्फ एम्स ही रहने देना चाहिए। इसके नाम को लेकर कोई भी फैसला एक राय से होना चाहिए। एम्स में सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम रहे तो ही बेहतर है।

जी की सहयोगी राजकुमारी अमृत कौर की दूरदर्शिता का नतीजा है। जिस निष्ठा और निस्वार्थ भाव से एम्स के डाक्टर रोगियों को देखते हैं, उससे तुरंत समझ आ जाता है कि ये सामान्य अस्पताल तो नहीं है।

एम्स पर लगता है, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के रोगियों का खासा यकीन है। यहां आने वाले कुल रोगियों में बिहारियों का आंकड़ा ही लगभग 50 फीसद होगा। पटना, दरभंगा, किशनगंज, अररिया, मुजफ्फरपुर वगैरह के तमाम रोगी एम्स दिल्ली से स्वस्थ होकर घर वापस जाते हैं। एम्स में काफी हद तक समाजवाद के दर्शन होते हैं।

अगर एम्स राजकुमारी अमृत कौर के विजन का परिणाम था, तो इसके पहले डायरेक्टर डॉ. बी.बी. दीक्षित (1902-1977) ने इसे एक श्रेष्ठ अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के रूप में स्थापित किया। वे एक महान डाक्टर, अनुभवी शिक्षक और कुशल प्रशासक थे। एम्स 1956 में स्थापित हुआ तो सरकार ने डॉ दीक्षित को इसका पहला निदेशक का पदभार संभालने की पेशकश की गई। उन्होंने इस पद को एक शर्त पर स्वीकार किया। उनका कहना था कि वे किसी नेता या बड़े सरकारी अफसर का नियुक्तियां में हस्तक्षेप नहीं स्वीकार करेंगे। वे एक ईमानदार और कड़क इंसान थे। वे पुणे के बी.जे. मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके थे। वे फिजीऑलजी (शरीर विज्ञान) विषय के प्रोफेसर भी थे। डॉ. दीक्षित ने अपने कार्यकाल में एम्स में चोटी के प्रोफेसरों/डाक्टरों को जोड़ा। वे हरेक नियुक्ति उम्मीदवार की योग्यता पर करते थे। वे लगातार एम्स में रिसर्च करने वालों को प्रोत्साहित करते रहते थे। डॉ. दीक्षित 1925 में मुंबई के ग्रांट मेडिकल कॉलेज के छात्र रहे थे। वे सत्य और न्याय का साथ देने वाले इंसान थे। उन्होंने देश को एम्स के रूप में एक विश्व स्तरीय संस्थान खड़ा कि दिया।

एम्स की स्थापना के लगभग एक दशक के बाद 1967 में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के नाम पर एम्स में राजेन्द्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ। इसका ध्येयवाक्य है 'तमसो मा ज्योतिर्गमय'। इसके पहले निदेशक प्रो.एल.पी अग्रवाल थे। वे अमेरिका के बोस्टन रेटिना सेंटर से उच्च शिक्षा प्राप्त करके आए थे। उन्होंने भी अनेकों कुशल नेत्र चिकित्सकों को इस केंद्र से जोड़ा।

एम्स की स्थापना के 66 सालों के बाद इसका नाम बदलने का कोई औचित्य समझ नहीं आता। इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। एम्स को तो सिर्फ एम्स ही रहने देना चाहिए। इसके नाम को लेकर कोई भी फैसला एक राय से होना चाहिए। एम्स में सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम रहे तो ही बेहतर है। इसका अभी तक का सफर बेहद गौरवपूर्ण रहा है। देश के बाकी सरकारी और निजी अस्पतालों को इसके कामकाज से सीखना होगा। सरकार के ऊपर भी यह दायित्व तो रहेगा कि वह देश के गांवों से लेकर महानगरों के अस्पतालों को एम्स जैसा ही स्तरीय बनाए। सबसे पहले तो यह प्रयास करना होगा ताकि निजी अस्पताल मरीजों को भयभीत न करें। उनसे नए-नए टेस्ट करवाने के लिए न कहें। अगर किसी रोगी को अस्पताल में भर्ती करना ही है तो उससे यह न पूछें कि क्या उसके पास इंश्योरेंस है?

(लेखक वरिष्ठ संपादक, स्तभकार और पूर्व सांसद हैं)

सशस्त्र संघर्ष के महानायकों की संघर्ष गाथा को बताती झांसी फाइल्स, काशी और मित्र मेला

आजादी के महायज्ञ में मां भारती के अनेकों वीर सपूतों ने अपने जीवन का सर्वस्व न्योछावर कर दिया परंतु आजादी के बाद भारत की इस संघर्ष गाथा को जब कलमबद्ध किया जाने लगा तो आजादी के सभी महानायकों के साथ न्याय नहीं हो सका। इतिहास लेखन में एक विचारधारा विशेष के लोगों के हावी होने के चलते अहिंसक आंदोलन के प्रणेता महात्मा गांधी और उनके अनुयायियों के संघर्ष को तो भावी पीढ़ी के लोगों को बताया गया परंतु इसी दौरान सशस्त्र संघर्ष के द्वारा ब्रिटिश सरकार की चूलें हिलाने वालों महा नायकों की संघर्ष गाथा को चंद अध्यायों में निपटा दिया गया।

आजादी के अमृत काल में भारत मां के वीर सपूतों के संघर्ष के इन अनछुए पहलुओं को आमजन तक पहुंचाने और भावी पीढ़ी को आजादी के इन महानायकों

की संघर्ष गाथा को बताने का बीड़ा उठाया है वरिष्ठ लेखक डॉ मनीष श्रीवास्तव ने।

डॉक्टर श्रीवास्तव ने अपने पहले प्रयास के तहत सशस्त्र संघर्ष के नायकों चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र नाथ सान्याल, मन्मथनाथ, जैसे सूर वीरों की संघर्ष गाथा को तीन पुस्तकों झांसी फाइल्स, काशी और मित्र मेला के जरिए प्रस्तुत किया है। डॉक्टर श्रीवास्तव के लेखन की खास बात यह है कि यह पुस्तकें उनके पूर्वजों की आजादी के महानायकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर किए गए संघर्ष एवं उनके द्वारा लेखक को बताए अनुभव पर आधारित है।

झाँसी फाइल्स की कहानी शुरू होती है 1926 के आसपास, जिसमे आज़ाद के अज्ञातवास के झाँसीवास के बारे में बताया गया है। जिसके बारे में आम जन को अब तक ज्यादा जानकारी नहीं है। चूँकि आज़ाद का अज्ञातवास लेखक के नाना श्री रुद्रनारायण के निवास से शुरू हुआ था, इसलिए इन प्रसंगों की अधिक जानकारी लेखक को है। इसी दौरान ज़िक्र आता है आज़ाद साहब के कुछ और साथियों भगवान् दास माहौर, सदाशिव मल्कापुरकर और विश्वनाथ वैशम्पायन जी का, जो आज़ाद से अंतिम समय तक जुड़े रहे थे। यह कहानी झाँसी और ओरछा के आसपास घूमती रहती है।

लेखक की दूसरी पुस्तक 'काशी' में आज़ाद के काशी प्रवास के बारे में वर्णन है। इसमें भारत के आजादी के सशस्त्र संघर्ष के महानायक चंद्रशेखर आजाद की मुलाकात बंगाल के सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी सचिन्द्र नाथ सान्याल से होती है जहाँ वह अन्य सुप्रसिद्ध क्रांतिकारियों लाहिड़ी, बिस्मिल, प्रणवेश, मन्मथ साहब से आज़ादी के आन्दोलन की आगे की संघर्ष योजना पर चर्चा करते दिखते हैं । शेखर के आज़ाद बनने की कहानी भी आपको इसी अंक में मिलने वाली है। इसके साथ ही इसमें बिस्मिल के पहले गुरु पंडित गेंदा लाल जी के दुखभरे अंत का ज़िक्र किया गया है ।

मित्रमेला की कहानी शुरू होती है अविभाजित भारत में क्रांतिकारी संघर्ष के बड़े केंद्र में शुमार रहे लाहौर से। मित्र मेला में कहानी शुरू होती है भगत सिंह सुखदेव राजगुरु भाई परमानंद जय चंद्र और जुगल किशोर जी जैसे नामी क्रांतिकारियों के वैचारिक प्रशिक्षण से। जान नेशनल कॉलेज यस आजादी के यह महानायक जय चंद्र जी और जुगल किशोर जी जैसे नामी अध्यापकों और शिक्षाविदों से अपना वैचारिक आधार प्राप्त करते हैं। वीर सावरकर स के जीवन से शुरू हुई कहानी उनके साथियों से मिलाती हुई आप को लंदन ले जायेगी।

राजनीतिक तरकश
देश का सबसे तेज साप्ताहिक
राष्ट्रीय विचार, सटीक समाचार
8
वर्ष : 01 , अंक : 03, नई दिल्ली, बुधवार, 12 अक्टूबर, 2022

जनता को अनधिकृत मोबाइल ऐप से सावधान रहना चाहिए

सवांददाता

आज के दिन आपके सामने अवैध लोन ऐप की भरमार है। दरअसल देशभर में ऐप्स के जरिए अवैध रूप से कर्ज देने वाली सैंकड़ों कंपनियां ठगी कर जरिया बन रही हैं। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने भी देश में अवैध लोन ऐप्स के धंधे को लेकर अहम बैठक की थी। इस बैठक में माना गया कि ये एप्स भारतीय रिजर्व बैंक के नियम, कानून के दायरे से बाहर रहकर बड़े पैमाने पर कर्ज बांट रहे हैं। साथ ही लोगों को डरा-धमकाकर ऊंची ब्याज दरों पर वसूली कर रहे हैं। अवैध ऋण एप्स की ठगी का शिकार लोगों के आत्महत्या के मामले भी सामने आ रहे हैं। ईडी के छापों में काली कमाई के नेटवर्क का भंडाफोड़ भी हुआ है। मुद्दा गंभीर है आपसे जुड़ा है इसलिए अवैध ऋण एप्स के इस पूरे मामले को समझना। जानना जरूरी है। डिजिटल लोन में प्रमाणीकरण और क्रेडिट मूल्यांकन के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर वेब प्लेटफॉर्म या मोबाइल ऐप के माध्यम से उधार देना शामिल है। बैंकों ने पारंपरिक उधार में मौजूदा क्षमताओं का लाभ उठाकर डिजिटल ऋण बाजार में टैप करने के लिए अपने स्वयं के स्वतंत्र डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं। यह भारत में विशेष रूप से सूक्ष्म उद्यम और निम्न-आय वाले उपभोक्ता खंड में बड़ी अधूरी ऋण आवश्यकता को पूरा करने में मदद करता है। यह अनौपचारिक उधार को कम करने में मदद करता है क्योंकि यह उधार लेने की प्रक्रिया को सरल करता है। यह शाखा में कार्य ऋण आवेदनों पर खर्च किए गए समय को कम करता है। डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म को ओवरहेड लागत में 30-50% की कटौती करने के लिए भी जाना जाता है।

मगर इस बात का फायदा उठाकर अनधिकृत डिजिटल लेंडिंग प्लेटफार्म और मोबाइल एप्लिकेशन की बढ़ती संख्या चिंता का कारन बनी है। वे अत्यधिक ब्याज दर और अतिरिक्त छिपे हुए शुल्क लेते हैं। वे अस्वीकार्य और उच्च-स्तरीय पुनर्प्राप्ति विधियों को अपनाते हैं। वे उधारकर्ताओं के मोबाइल फोन पर डेटा तक पहुंचने के लिए समझौतों का दुरुपयोग करते हैं। जनता को अनधिकृत डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप से सावधान रहना चाहिए।

जनता को ऑनलाइन या मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण देने वाली कंपनी/फर्म के पूर्ववृत्त का सत्यापन करना चाहिए। उपभोक्ताओं को कभी भी केवाईसी दस्तावेजों की प्रतियां अज्ञात व्यक्तियों या असत्यापित/अनधिकृत ऐप्स के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। वे ऐप से जुड़े ऐसे ऐप/बैंक खाते की जानकारी संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों को रिपोर्ट कर सकते हैं या शिकायत दर्ज करने के लिए सचेत पोर्टल (ँ३३स्र२://ट्टी३.१.ड्ड्र्ढ्ढ.ल्ल) का उपयोग कर सकते हैं। डिजिटल लेंडिंग ऐप्स को लेकर बहुत सी समस्याएं हैं। वे जल्दी और परेशानी मुक्त तरीके से ऋण के वादे के साथ उधारकर्ताओं को आकर्षित करते हैं। लेकिन, उधारकर्ताओं से अत्यधिक ब्याज दर और अतिरिक्त छिपे हुए शुल्क की मांग की जाती है। ऐसे प्लेटफॉर्म अस्वीकार्य और उच्च-स्तरीय पुनर्प्राप्ति विधियों को अपनाते हैं। वे उधारकर्ताओं के मोबाइल फोन पर डेटा तक पहुंचने के लिए समझौतों का दुरुपयोग करते हैं।

गूगल अपने एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले 95% स्मार्टफोन के साथ भारत के ऐप बाजार पर हावी है, गूगल को भारत सरकार और केंद्रीय बैंक द्वारा भारत में अवैध डिजिटल ऋण देने वाले अनुप्रयोगों के उपयोग को रोकने में मदद करने के लिए और अधिक कड़े चेक पेश करने के लिए कहा है। भले ही गूगल भारतीय रिजर्व बैंक के दायरे में नहीं आता है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में केंद्रीय बैंक और भारत सरकार की बैठकों में यू.एस. टेक दिग्गज को कई बार बुलाया गया है और सख्त चेक और बैलेंस पेश करने का आग्रह किया गया है। जो ऐसे ऐप्स को बाहर निकालने में मदद कर सकता है। भारतीय नियामकों ने पहले ही उधारदाताओं को अवैध उधार देने वाले ऐप्स के खिलाफ जांच करने के लिए कहा है, जो महामारी के दौरान लोकप्रिय हो गए थे। नियामक ऐसे ऐप्स के प्रसार को नियंत्रित करना चाहते हैं जो अनैतिक गतिविधियों में संलग्न हैं जैसे कि अत्यधिक ब्याज दर और शुल्क वसूलना या वसूली प्रथाओं में जो केंद्रीय बैंक द्वारा अधिकृत नहीं हैं या मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हैं।

> अनधिकृत डिजिटल लेंडिंग प्लेटफार्म और मोबाइल एप्लिकेशन की बढ़ती संख्या चिंता का कारण बनी है। वे अत्यधिक ब्याज दर और अतिरिक्त छिपे हुए शुल्क लेते हैं। वे अस्वीकार्य और उच्च-स्तरीय पुनर्प्राप्ति विधियों को अपनाते हैं। वे उधारकर्ताओं के मोबाइल फोन पर डेटा तक पहुंचने के लिए समझौतों का दुरुपयोग करते हैं। जनता को अनधिकृत डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप से सावधान रहना चाहिए। जनता को ऑनलाइन या मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण देने वाली कंपनी/फर्म के पूर्ववृत्त का सत्यापन करना चाहिए। उपभोक्ताओं को कभी भी केवाईसी दस्तावेजों की प्रतियां अज्ञात व्यक्तियों या असत्यापित/अनधिकृत ऐप्स के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। वे ऐप से जुड़े ऐसे ऐप/बैंक खाते की जानकारी संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों को रिपोर्ट कर सकते हैं या शिकायत दर्ज करने के लिए सचेत पोर्टल (ँ३३स्र२://ट्टी३.१.ड्ड्र्ढ्ढ.ल्ल) का उपयोग कर सकते हैं।

लोगों को 'इस तरह की बेईमान गतिविधियों' के शिकार होने के खिलाफ चेतावनी देते हुए, आरबीआई ने कहा, 'वैध सार्वजनिक ऋण गतिविधियों को बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा आरबीआई और अन्य संस्थाओं द्वारा पंजीकृत किया जा सकता है जो वैधानिक प्रावधानों जैसे संबंधित राज्यों के धन उधार अधिनियम के तहत राज्य सरकारों द्वारा विनियमित होते हैं। भारत एक डिजिटल ऋण क्रांति के कगार पर है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि यह ऋण जिम्मेदारी से किया जाता है। डिजिटल ऋणदाताओं को सक्रिय रूप से एक आचार संहिता विकसित और प्रतिबद्ध करनी चाहिए जो प्रकटीकरण और शिकायत निवारण के स्पष्ट मानकों के साथ अखंडता, पारदर्शिता और उपभोक्ता संरक्षण के सिद्धांतों को रेखांकित करती है। तकनीकी सुरक्षा उपायों को स्थापित करने के अलावा, डिजिटल उधार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ग्राहकों को शिक्षित और प्रशिक्षित करना भी महत्वपूर्ण है। डिजिटल लेंडिंग ऐप्स को हितधारकों के परामर्श से स्थापित की जाने वाली नोडल एजेंसी द्वारा सत्यापन प्रक्रिया के अधीन किया जाना चाहिए। डिजिटल लेंडिंग इकोसिस्टम में प्रतिभागियों को शामिल करते हुए एक स्व-नियामक संगठन (एसआरओ) की स्थापना करना इस समस्या को सुलझा सकता है।

डिजिटल ऋणों के लिए अवांछित वाणिज्यिक संचार का उपयोग प्रस्तावित एसआरओ द्वारा लागू की जाने वाली आचार संहिता द्वारा नियंत्रित किया जाए। प्रस्तावित एसआरओ द्वारा ऋण सेवा प्रदाताओं की 'नकारात्मक सूची' का रखरखाव, ऋणों का संवितरण सीधे उधारकर्ताओं के बैंक खातों में होना चाहिए।

सभी डेटा भारत में स्थित सर्वरों में संग्रहित किया जाये और दस्तावेजीकरण के लिए डिजिटल उधार में उपयोग की जाने वाली एल्गोरिथम विशेषताओं को आवश्यक पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए। ग्राहक सुरक्षा को बढ़ाते हुए और डिजिटल ऋण देने वाले पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित और नवीन बनाते हुए अधिक वैध उधारदाताओं को प्रोत्साहित करें। भारत में डिजिटल उधार बाजार तेजी से विकसित हो रहा है, और चौथी औद्योगिक क्रांति के साथ यह डिजिटल-भी से डिजिटल-प्रथम से केवल-डिजिटल में बदलाव का समय है। अब यह डिजिटल ऐप्स पर निर्भर है कि वे नियमों से खेलें और खुद को सेल्फ रेगुलेट करें।

आरबीआई को वास्तविक समय के आधार पर उधार देने वाले ऐप्स को ट्रैक करने के लिए आवश्यक आवश्यक तकनीक और तकनीकी विशेषज्ञता से लैस होना चाहिए।

सिर्फ औरतें ही अपना मुंह क्यों छिपाएं ?

सवांददाता

मुस्लिम औरतें हिजाब पहने या नहीं, इस मुद्दे को लेकर ईरान में जबर्दस्त कोहराम मचा हुआ है। जगह-जगह हिजाब के विरुद्ध प्रदर्शन हो रहे हैं। कई लोग हताहत हो चुके हैं। तेहरान विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने हड़ताल कर दी है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खोमनई के खिलाफ खुले-आम नारे लग रहे हैं। विभिन्न शहरों और गांवों में हजारों पुलिसवाले तैनात कर दिए गए हैं। ऐसा लग रहा है कि ईरान में शहंशाह के खिलाफ जो माहौल सन 1975-78 में देखने में आया था, उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। कई बड़े शिया नेता भी हिजाब का विरोध करने लगे हैं। यह कोहराम इसलिए शुरू हुआ है कि महसा आमीनी (22 साल) नामक युवती को तेहरान में गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि उसने हिजाब नहीं पहना हुआ था। गिरफ्तारी के तीन दिन बाद 16 सितंबर को जेल में ही उसकी मौत हो गई। उसके सिर तथा अन्य अंगों पर भयंकर चोट के निशान थे। इस दुर्घटना ने ईरान की महिलाओं में रोष फैला दिया है। हजारों छात्राओं ने अपना हिजाब उतारकर फेंक दिया। आयतुल्लाह खुमैनी के शासन (1979) के पहले और बाद में मुझे ईरान में रहने और पढ़ाने के कई मौके मिले। शहंशाह-ईरान के राज में औरतों की वेश-भूषा में इतनी छूट थी कि तेहरान कभी-कभी लंदन और न्यूयार्क की तरह दिखाई पड़ता था। मेरे इस्लामी मित्रों में कई नेता, प्रोफेसर, पत्रकार और आयतुल्लाह भी थे। वे कहा करते थे कि हम शिया मुसलमान हैं। हम आर्य हैं। हम अरबों की नकल क्यों करें? अब तो ईरान में कट्टर इस्लामी राज है लेकिन लोग खुले-आम कह रहे हैं कि हिजाब, बुर्का, नकाब या अबाया को कुरान-शरीफ में कहीं भी जरुरी नहीं बताया गया है। इसके अलावा डेढ़ हजार साल पहले अरब देशों में जो वेशभूषा, भोजन और जीवन-पद्धति थी, उसकी आज भी हू-ब-हू नकल करना कहाँ तक ठीक है? यूरोप के तो कई देशों में हिजाब और बुर्के पर कड़ी पाबंदी है। जो इस पाबंदी को नहीं माने, उसको दंडित भी किया जाता है। बुर्के और हिजाब में चेहरा छिपाकर बहुत-से आतंकवादी, तस्कर और अपराधी लोग अपना काम-धंधा जारी रखते हैं। वास्तव में बुर्का और हिजाब तो स्त्री-जाति के अपमान का प्रतीक है। असली सवाल यह है कि सिर्फ औरतें ही अपना मुँह क्यों छिपाएँ? यह नियम मर्दों पर भी लागू क्यों नहीं किया जाता? यदि यह इस्लामी नियम है तो मैं पूछता हूं कि क्या बेनजीर भुट्टो, मरियम नवाज और इंडोनेशिया की सुकर्ण-पुत्री मेघावती मुसलमान नहीं मानी जाएंगी? यदि यही नियम सख्ती से लागू किया जाए तो सारे सिनेमा घर बंद करने होंगे। इस्लामी देश तो कला के कब्रिस्तान बन जाएंगे। इसीलिए लगभग दर्जन भर इस्लामी देशों में हिजाब और बुर्का वगैरह को हतोत्साहित किया जाता है। भारत के स्कूल की छात्राओं के लिए भी हिजाब की मांग करना सर्वथा अनुचित है। ईरान की इस्लामी सरकार अपने आप को देश और काल के अनुरुप बनाए, यह बेहद जरुरी है। वरना वे लोगों को इस्लाम के प्रति उदासीन कर देंगे।

> असली सवाल यह है कि सिर्फ औरतें ही अपना मुँह क्यों छिपाएँ? यह नियम मर्दों पर भी लागू क्यों नहीं किया जाता? यदि यह इस्लामी नियम है तो मैं पूछता हूं कि क्या बेनजीर भुट्टो, मरियम नवाज और इंडोनेशिया की सुकर्ण-पुत्री मेघावती मुसलमान नहीं मानी जाएंगी? यदि यही नियम सख्ती से लागू किया जाए तो सारे सिनेमा घर बंद करने होंगे। इस्लामी देश तो कला के कब्रिस्तान बन जाएंगे। इसीलिए दर्जन भर इस्लामी देशों में हिजाब और बुर्का वगैरह को हतोत्साहित किया जाता है। भारत के स्कूल की छात्राओं के लिए भी हिजाब की मांग करना सर्वथा अनुचित है। ईरान की इस्लामी सरकार अपने आप को देश और काल के अनुरुप बनाए, यह बेहद जरुरी है। वरना वे लोगों को इस्लाम के प्रति उदासीन कर देंगे।